गन्ने की ऊंची कीमत के कारण पेराई नहीं करने का फैसला

यूपी की शुगर मिलें काम शुरू करने के मूड में नहीं

[ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली & लखनऊ]

उत्तर प्रदेश के शुगर मिल मालिकों ने नए सीजन में मिलों को बंद रखने का फैसला किया है। मिल मालिकों का कहना है कि चार साल तक नुकसान झेलने के बाद अब उनके पास ऑपरेशन चलाने की ताकत नहीं बची है। उनके मुताबिक, राज्य सरकार ने गन्ने की कीमत 70 फीसदी तक बढ़ा दी है, जबकि शुगर की कीमत में महज 7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, राज्य सरकार अक्टूबर से पेराई शुरू करने और गन्ना किसानों की बकाया राशि के भुगतान को लेकर आमादा नजर आ रही है, लिहाजा बजाज हिंदुस्तान की मिल कुशाग्र बजाज, सिम्भावली शुगर्स के गुरसिमरन मान, त्रिवेणी के तरुण साहनी, बलरामपुर चीनी के विवेक सरावगी और कुछ अन्य का सरकार से सीधा टकराव हो सकता है। यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन (यूपीएसएमए) ने इस सिलसिले में राज्य के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है, 'शुगर मिलें गन्ना पेराई ऑपरेशन स्थगित करने को लेकर नोटिस जारी कर रही हैं। मिलें अपनी प्लांट और मशीनरी के मेंटनेंस और मरम्मत का काम छोड़ने को मजबूर हैं। उसी के हिसाब से चीनी मिलें स्टाफ, अधिकारी और लेबर को हटा रही हैं।'

> "शुगर मिलें गन्ना पेराई ऑपरेशन स्थगित करने को लेकर नोटिस जारी कर रही हैं। मिलें अपनी प्लांट और मशीनरी के मेंटनेंस और मरम्मत का काम छोड़ने को मजबूर हैं। उसी के हिसाब से चीनी मिलें स्टाफ, अधिकारी और लेबर को हटा रही हैं
>
> **यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन**

चीनी मिलें चाहती हैं कि यूपी में गन्ने की कीमत को शुगर प्राइस से लिंक किया जाए, जैसा महाराष्ट्र और कर्नाटक में हो चुका है। देश में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत उत्तर प्रदेश में है। राज्य सरकार ने मिलों को 280 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर किसानों से गन्ना खरीदने का निर्देश दिया है। राज्य में गन्ना किसानों को मिलों से 7,000 करोड़ रुपये लेने हैं। शुगर इंडस्ट्री को करेंट सीजन के खत्म होने तक यह राशि 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने मिलों की डिमांड को अनुचित बताया है। यूपी के केन कमिश्नर सुभाष चंद शर्मा ने बताया, 'इस मसले का हल निकालने के लिए सरकार और प्राइवेट मिलें बात कर सकती हैं। शुगर मिलों की कुछ मांगें अनुचित हैं। किसानों की भी चिंताएं हैं, जिनका खयाल सरकार को रखना होगा। यूपी उत्तर भारतीय राज्य है और यहां के गन्ने की कीमत की तुलना उत्तराखंड और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों से नहीं की जा सकती...और न ही महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ने की कीमत से। आखिरकार फैसला सरकार ही लेगी। फिलहाल, मैं इतना ही कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर इस सीजन में चीनी मिलें अपना काम शुरू करेंगी।' महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य पहले ही गन्ने की कीमत तय किए जाने के बजाय किसानों के साथ रेवेन्यू शेयर करने जैसे फॉर्मूले को अपना चुके हैं। शुगर प्रॉडक्शन में दोनों राज्यों की हिस्सेदारी तकरीबन 50 फीसदी है। दोनों यूपी की शुगर इंडस्ट्री ने किसानों को 75 फीसदी रेवेन्यू देने की सिफारिश की है, जिससे गन्ने की कीमत 240-250 रुपये प्रति क्विंटल बैठेगी।

> **चीनी मिलें** चाहती हैं कि यूपी में गन्ने की कीमत को शुगर प्राइस से लिंक किया जाए, जैसा महाराष्ट्र और कर्नाटक में हो चुका है

इकनोमिक टाइम्स
6/8/14